नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से
भोपाल 70 वां वर्ष संस्करण

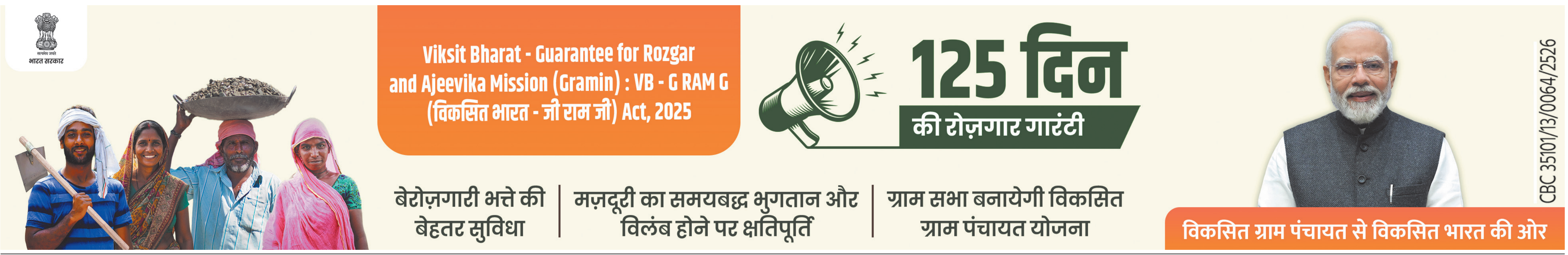

एआई पर बातचीत ज्ञानवर्धक

स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह निर्माता : मोदी

नई दिल्ली, 8 जनवरी. भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ की राउंडटेबल चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि स्टार्टअप्स के साथ एआई पर बातचीत यादगार और ज्ञानवर्धक रही. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, भारतीय स्टार्टअप जगत के युवाओं के साथ एआई पर चर्चा हुई.

यह एक यादगार और ज्ञानवर्धक बातचीत थी, जिसमें उन्होंने भारत द्वारा एआई की दुनिया को बदलने के प्रयासों के बारे में अपने दृष्टिकोण और कार्यों को साझा किया. यह सराहनीय है कि ये स्टार्टअप ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग

सिमुलेशन, सामग्री अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा अनुसंधान और अन्य विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सुबह भारतीय एआई स्टार्टअप के साथ बैठक की. यह बैठक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले हुई है, जो कि अगले महीने भारत में होने वाला है.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वह 12 एआई स्टार्टअप शामिल हुए हैं, जिन्होंने एआई फॉर ऑल: ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए क्वालिफाई किया है.

> प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है. इस कारण भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए. साथ ही कहा कि भारत किफायती एआई, समावेशी एआई और किफायती इनोवेशन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे सकता है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल विशिष्ट होने चाहिए और स्थानीय एवं स्वदेशी सामग्री तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने वाले हो. इस बैठक में अवतार, भारतजेन, फ्रैक्टल, गैन, जेनलोप, ज्ञानी, इंटेलीहेल्थ, सर्वम, शोध एआई, सॉकेट एआई, टेक महिंद्रा और जेंटिक सहित भारतीय एआई स्टार्टअप्स के सीईओ, प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल हुए. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी बैठक में उपस्थित थे.

बैठक में पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निर्माता हैं और कहा कि देश में इनोवेशन और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन दोनों की अपार क्षमता है. उन्होंने आगे कहा कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसा अनूठा एआई मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए जो मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना को दर्शाता हो.

इंदौर : ओपीडी में पहुंचे 23 नए मरीज 6 की हालत गंभीर

नव भारत न्यूज

इंदौर, 8 जनवरी. डायरिया प्रभावित भागीरथपुरा क्षेत्र में गुरुवार को एक बार फिर मरीजों की संख्या बढ़ी है. ओपीडी में 23 नए मरीज सामने आए, जिनमें से 6 की हालत को देखते हुए रेफर किया. जबकि पहले से ही 10 मरीज आईसीयू में भर्ती होकर इलाजरत हैं, जबकि 50 मरीज वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बताए जा रहे हैं. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि गुरुवार को समाचार लिखे जाने तक अस्पतालों में 446 मरीज इलाज करवाने पहुंचे थे, इनमें से 396 मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है. फिलहाल 10 आईसीयू में इलाजरत हैं. जबकि गुरुवार को ओपीडी में आए 23 नए मरीजों में यह भी सामने आया कि कई मरीज दवाइयों का निर्धारित डोज पूरा नहीं कर रहे हैं, जिससे बीमारी दोबारा उभरने की आशंका बनी हुई है.

सीएम आज बहरी में देंगे 201 करोड़ की सौगात

179 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 8 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को सीधी जिले के बहरी में आयोजित विभिन्न विभागों के हितग्राहियों के प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में 201 करोड़ 64 लाख रुपये के 209 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री 68 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 179 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 133 करोड़ 62 लाख रुपये लागत के 30 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे.

डॉ. यादव एक बगिया मां के नाम योजना में 505 हितग्राहियों को 11 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि से लाभान्वित करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा बहरी में अनुसूचित जाति विभाग, आदिवासी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, जिला पंचायत वाटरशेड, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के तहत कुल 179 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा. इन कार्यों पर 68 करोड़ एक लाख 40 हजार रुपये की लागत व्यय की गई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास को मजबूती मिलेगी.

एक नजर में

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में नेशनल पार्क कूनो में अफ्रीका के नामीबिया से लाये गये चीतों को छोड़ा. भारत में चीतों की वापसी से अब जैव विविधता की टूटी कड़ी पुनः जुड़ गई है। भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जाग्रत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की पहली बड़े जंगली मांसाहारी जीव की अंतर-महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना का चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुभारंभ करते हुए कहा कि सौभाग्य से हमें दशकों पहले जैव-विविधता की टूटी और विलुप्त कड़ी को जोड़ने का फिर से मौका मिला है। भारत की धरती पर चीता लौट आया है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है, जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृतकाल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है।

असम से आएंगे गैंडे के दो जोड़े

कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे उपयुक्त क्षेत्र

देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया कि कान्हा टाइगर रिज़र्व जंगली भैंसों के पुनःस्थापन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। अध्ययन में घास के मैदानों की गुणवत्ता, जल स्रोतों की उपलब्धता, मानव हस्तक्षेप की न्यूनता और अन्य शाकाहारी जीवों के दबाव जैसे कारकों का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, कान्हा के विस्तृत घास मैदानों में पहले भी जंगली भैंसों से आबाद रही है। योजना के तहत जंगली भैंसों को असम से मध्यप्रदेश लाने का प्रस्ताव है। आनुवांशिक विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि मध्यप्रदेश से विलुप्त रूप से हुई प्रजाति और असम एवं छत्तीसगढ़ की जंगली भैंसों में आनुवांशिक अंतर अत्यन्त कम है। इससे इनका मध्यप्रदेश के जंगलों में स्थानांतरण वैज्ञानिक रूप से भी व्यावहारिक है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) तथा भारत सरकार से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

मध्यप्रदेश एक बार फिर जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई मिसाल कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में विलुप्त हो चुकी जंगली भैंस प्रजाति को पुनर्स्थापित करने की वैज्ञानिक पहल अब अंतिम चरण में पहुँच गई है। जंगली भैंसों को असम से मध्यप्रदेश लाने की योजना है। असम से गैंडे के दो जोड़े भी प्रदेश में आयेंगे। इन्हें भोपाल के वन विहार में रखा जायेगा। मध्यप्रदेश वन विभाग बदले में असम की मांग के अनुसार 3 टाइगर और 6 मगरमच्छ स्थानांतरित करेंगे। असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और श्री हिमंता विश्व सरमा के बीच हुई बैठक में इस आदान-प्रदान पर चर्चा हुई। इस अवसर पर दोनों राज्यों के वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि चीते के बाद अब भैंस पुनर्स्थापना से प्रदेश की जैव विविधता में एक नया आयाम जुड़ेगा. यह प्रयास एक प्रजाति के संरक्षण के साथ ही प्रदेश के जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्यप्रदेश पहले ही 'टाइगर स्टेट' और 'लेपर्ड स्टेट' के रूप में अपनी पहचान बना चुका है।

सफल चीता पुनर्स्थापना के बाद जंगली भैंसों का पुनर्स्थापन से राज्य के जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ेगा। राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण के साथ ही उन प्रजातियों की वापसी के लिए भी प्रतिबद्ध है, जो कभी इस भूमि की पहचान हुआ करती थीं। मध्यप्रदेश में जंगली भैंसों की आबादी पिछले सौ वर्षों से भी अधिक समय पहले समाप्त हो चुकी थी। अत्यधिक शिकार, मानव का जंगलों में अवैध दखल, आवास का क्षरण और घास के मैदानों का नष्ट होना इसके प्रमुख कारण रहे। वर्तमान समय में देश में जंगली भैंसों की प्राकृतिक आबादी मुख्य रूप से असम राज्य तक सीमित रह गई है। छत्तीसगढ़ में भी ये हैं, किंतु इनकी संख्या अत्यन्त सीमित रह गई है।

पुनर्स्थापन को चरणबद्ध और सुरक्षित ढंग से अंजाम दिया जाएगा। शुरुआती तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 12 से 15 जंगली भैंसों को लाया जाएगा। इन्हें प्रारंभ में शिकारी-रोधी बाड़ों में रखा जाएगा। इनके लिये बाड़ों का निर्माण फरवरी 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना दीर्घकालिक संरक्षण और प्राकृतिक प्रजनन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जंगली भैंसों की वापसी से कान्हा और आसपास के जंगलों में घास आधारित पारिस्थितिकी तंत्र सशक्त बनेगा। यह अन्य शाकाहारी जीवों के लिए भी लाभकारी होगा, साथ ही मांसाहारी जीवों के प्राकृतिक व्यवहार और खाद्य श्रृंखला को भी संतुलित करेगा।

कान्हा में घास के मैदान जंगली भैंसों के पुनर्प्रवेश के लिए उपयुक्त

देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों के पुनर्प्रवेश की व्यवहार्यता का व्यवस्थित आंकलन करने के बाद बताया कि इसके लिए प्रजाति का उसके मौजूदा वितरण क्षेत्र के अन्य भागों में अध्ययन आवश्यक है और कान्हा टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिक उपयुक्तता का मूल्यांकन होना चाहिए. कान्हा में घास के मैदान जंगली भैंसों के पुनर्प्रवेश के लिए उपयुक्त पाए गए। जंगली भैंसों की अधिकांश आबादी असम राज्य में पाई जाती है। वर्तमान में केवल एक ही बची-खुची आबादी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में है। जंगली भैंसों की यही आबादी समय-समय पर महाराष्ट्र राज्य के पड़ोसी हिस्सों में चली जाती है। इसलिए यह प्रस्ताव है कि मध्य प्रदेश में लाने के लिए प्रारंभिक तौर पर असम राज्य से ही भैंसें लाई जाएंगी। डब्ल्यूआईआई ने अपने अध्ययन में प्रस्ताव दिया है कि शुरुआत में 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 12-15 भैंसों को संस्थापक समूह के रूप में लाया जाएगा। जंगली भैंसों को कान्हा में बाड़े में रखा जाएगा। लगभग 20 प्रजनन करने वाली मादा और 5 नर भैंसों को प्रजनन के लिए शिकारी-रोधी बाड़े में ही रखा जाएगा। मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक असम के माँग के अनुसार तीन (3) बाघ और छह (6) मगरमच्छ स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं।

> असम की जंगली भैंसों को मध्य प्रदेश में पुनः लाया जा सकता है। कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों को लाने का प्रस्ताव है क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक रूप से इस प्रजाति का निवास स्थान रहा है और स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के घास के मैदानों को भैंस जैसे खुरदुरा घास चरने वाले जानवर की उपस्थिति से काफी लाभ होगा। इस प्रजाति के विलुप्त होने से यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिक स्थान खाली हो गया है।

औद्योगिक विकास

असम के राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

कृषि के बाद टेक्सटाइल सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वस्त्र उद्योग विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की ओर बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में हैंडलूम और हैंडीक्रॉफ्ट को लेकर महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग को रोजगारपरक औद्योगिक विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश को औद्योगिक और निवेश की दृष्टि से उल्लेखनीय सहयोग मिला है। मध्यप्रदेश के धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क स्थित है, वहां पर टेक्सटाइल पार्क और उद्योगों का लोकार्पण भी किया जाएगा। यह पार्क भारत को सशक्त बनाने के संकल्प की पूर्ति भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत आर्थिक रूप से तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने के ओर अग्रसर है। मां कामाख्या की धरती असम से आज देश के वस्त्र उद्योग को नई दिशा प्राप्त होगी। सभी राज्यों में वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारत का वस्त्र उद्योग- विकास, विरासत और नवाचार का ताना-बाना की थीम पर आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की सराहना भी की.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संस्कृति, संस्कार, संसाधन और विरासत की दृष्टि से मध्यप्रदेश, टेक्सटाइल सहित अनेक उद्योगों में देश में अग्रणी है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक गतिविधियां और निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत संभाग और जिला स्तर पर भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से उज्जैन, रीवा, कटनी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में औद्योगिक विकास से जुड़ी गतिविधियों का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी जुलाई 2026 में भारत सरकार द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन में मध्यप्रदेश सरकार पार्टनर बनने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा है, उन्होंने केंद्रीय वस्त्र मंत्री को अगला सम्मेलन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में करने के लिए आग्रह किया।

इम्पैक्ट फीचर/D-13013/25